भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 289
05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई की उप-योजनाएं

289. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मात्स्यिकी के लिए गैर- पारंपरिक क्षेत्रों में कुल कितने क्षेत्र का विस्तार किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 2020 के दौरान 20,050 रुपये की आबंटित धनराशि का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पीएमएमएसवाई की किसी उपयोजना की घोषणा की है और उनमें निवेश किया है.

(घ) यदि हां, तो उक्त उप-योजनाओं का उद्देश्य क्या है; और

(ङ) क्या डीज़ल की ऊंची लागत और सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के कारण देश के मछुआरों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो उन्होंने एक दशक पहले कभी अनुभव नहीं की थी?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत (ससटेनेबल) और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20050 करोड़ रु/- के अभी तक के उच्चतम निवेश के साथ "प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)" नामक प्रमुख योजना लागू किया जा रहा है । पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 20823.40 हेक्टेयर मीठे पानी के तालाबों, 2855.59 हेक्टेयर लवणीय /क्षारीय तालाबों और 1370.86 हेक्टेयर खारे पानी के तालाबों के निर्माण तथा उच्च घनत्व जलीय कृषि गतिविधियाँ जैसे 3703.5 हेक्टेयर बायोफ्लॉक तालाबों के निर्माण के माध्यम से जलीय कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए सहायता प्रदान की गई है ।

(ख): 2020-21 के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत 2876.33 करोड़ रु/- (1084.72 करोड़ केंद्रीय हिस्सा) के निवेश को मंजूरी दी गई । कुल 699.72 करोड़ रुपये विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए, जिसमें से यह रिपोर्ट किया गया है कि 620.38 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) और (घ): जी हाँ । केंद्रीय बजट 2023-24 में, सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की एक नई उप-योजना की घोषणा की है ताकि मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को और सक्षम बनाया जा सके, मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार हो सके और बाजार का विस्तार हो । उप-योजना का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को धीरे-धीरे औपचारिक बनाना और क्षेत्र में संस्थागत वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना, मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार, गुणवत्ता आश्वासन, और सुरक्षित मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों की आपूर्ति और मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौकरियों के सृजन और उन्हें बनाए रखने हेतु सूक्ष्म उद्यमों और/या छोटे उद्यमों जैसे मूल्य श्रृंखला से जुड़े आयामों को प्रोत्साहित करना है । उप-योजना का उद्देश्य जलीय कृषि प्रणाली में संबंधित जोखिमों को दूर करने में सहायता करना भी है ।

(ङ): जी नहीं । मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

****